

पत्रांक—.....5861

न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

चैतन्य प्रसाद,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद् बक्सर।

पटना, दिनांक 21/8/16

विषय :- माह जुलाई 2016 की मासिक समीक्षा टिप्पणी के संबंध में।

महाशय,

नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा आपके कार्यों की मासिक समीक्षा की जा रही है। माह जुलाई तक प्राप्त प्रतिवेदनों की समीक्षा से निम्न तथ्य विदित होते हैं :-

1. **चतुर्थ राज्य वित्त आयोग :-**

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत दिनांक 01.04.2016 को आपके नगर निकाय में 65.02 लाख रुपये उपलब्ध थे। वर्ष 2016-17 में 0.00 लाख रुपये विमुक्त हुए। कुल उपलब्ध 65.02 लाख रुपये संसाधनों में से अद्यतन व्यय 28.93 लाख रुपये है। जो की 44.49 प्रतिशत है। स्पष्टतः आपकी उपलब्धि **असंतोषजनक** है।

2. **13वें वित्त आयोग :-**

(i) 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत दिनांक 01.04.2016 को आपके नगर निकाय में 212.80 लाख रुपये उपलब्ध थे। वर्ष 2016-17 में 0.00 लाख रुपये विमुक्त हुए। कुल उपलब्ध 212.80 लाख रुपये संसाधनों में से अद्यतन व्यय 80.16 है। जो 37.67 प्रतिशत है।

(ii) भौतिक प्रतिवेदन की समीक्षा करने से ज्ञात है कि दिनांक 01.04.2016 को 22 योजनाएं लंबित थीं। वर्ष 2016-17 में अब तक कोई भी योजना नहीं ली गयी है। इस प्रकार कुल कार्यरत 22 योजनाओं में से 16 योजनाएं पूर्ण हो गई है। स्पष्टतः आपकी उपलब्धि **संतोषजनक** है।

3. **14वें वित्त आयोग :-** 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत दिनांक 01.04.2016 को आपके नगर निकाय में 164.66 लाख रुपये उपलब्ध थे। वर्ष 2016-17 में 150.99 लाख रुपये विमुक्त हुए। कुल उपलब्ध 315.65 लाख रुपये संसाधनों में से अद्यतन व्यय 90.47 लाख रुपये है, जो की मात्र 28.66 प्रतिशत है। स्पष्टतः आपकी उपलब्धि **निराशाजनक** है।

4. **राज्य योजना :-**

(i) राज्य योजना अंतर्गत दिनांक 01.04.2016 को आपके नगर निकाय में 571.10 लाख रुपये उपलब्ध थे। वर्ष 2016-17 में 0.00 लाख रुपये विमुक्त हुए। कुल उपलब्ध 571.10 लाख रुपये संसाधनों में से अद्यतन व्यय 44.04 लाख रुपये है, जो की 7.71 प्रतिशत है।

- (ii) भौतिक प्रतिवेदन की समीक्षा करने से ज्ञात है कि दिनांक 01.04.2016 को 8 योजनाएं लंबित थीं। वर्ष 2016-17 में अब तक कोई भी योजना नहीं ली गयी है। इस प्रकार कुल कार्यरत 8 योजनाओं में से अभी तक 3 योजनाएं पूर्ण हुई हैं। स्पष्टतः आपकी उपलब्धि अत्यंत निराशाजनक है।

5. पंचम राज्य वित्त आयोग:-

पंचम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत दिनांक 01.04.2016 को आपके नगर निकाय में 381.95 लाख रुपये उपलब्ध थे। वर्ष 2016-17 में 0.00 लाख रुपये विमुक्त हुए। कुल उपलब्ध 381.95 लाख रुपये संसाधनों से अद्यतन व्यय 30.34 लाख रुपये है, जो मात्र 7.94 प्रतिशत है। स्पष्टतः आपकी उपलब्धि अत्यंत निराशाजनक है।

6. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF):-

- (i) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अंतर्गत दिनांक 01.04.2016 को आपके नगर निकाय में 36.43 लाख रुपये उपलब्ध थे। वर्ष 2016-17 में 0.00 लाख रुपये विमुक्त हुए। कुल उपलब्ध 36.43 लाख रुपये संसाधनों में से अद्यतन व्यय 0.00 लाख रुपये है। जो की मात्र 0.00 प्रतिशत है।

- (ii) भौतिक प्रतिवेदन की समीक्षा करने से ज्ञात है कि दिनांक 01.04.2016 को कोई योजनाएं लंबित नहीं थीं। वर्ष 2016-17 में अब तक कोई भी योजना नहीं ली गयी है। अतः उपलब्ध संसाधनों में से नयी योजनाओं का चयन करते हुए कार्यों का निष्पादन करें। स्पष्टतः आपकी उपलब्धि अत्यंत निराशाजनक है।

7. ठोस अवशिष्ट प्रबंधन :-

- (i) आपके शहर में कुल 34 वार्ड हैं, जिसमें से 18 वार्ड में डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण का कार्य हो रहा है।
- (ii) सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए यांत्रिकरण पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन वांछित संख्या में मशीनों का क्रय नहीं किया गया है। शहर में कार्यरत सफाई कर्मियों की ससमय उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बायोमिट्रिक हाजिरी व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है, इसका अनुपालन अप्राप्त है। ठोस अवशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन एवं निष्पादन के लिए की जा रही कार्रवाई का प्रतिवेदन अपेक्षित है।

8. मुख्यमंत्री स्वच्छता अनुदान :- मुख्यमंत्री स्वच्छता अनुदान योजना के अंतर्गत दिनांक 01.04.2015 को आपके नगर निकाय में 0.00 लाख रुपये उपलब्ध थे। वर्ष 2015-16 में 100.26 लाख रुपये विमुक्त हुए। कुल उपलब्ध 100.26 लाख रुपये संसाधनों में से दूरभाष पर प्राप्त सूचना के अनुसार अद्यतन व्यय 87.00 लाख रुपये है।

9. उपयोगिता प्रमाण पत्र :-

आपके निकाय के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2003-04 से 2014-15 तक की अवधि में कुल 2646.17 लाख की राशि विभाग द्वारा आवंटित की गयी थी जिसके आलोक में अभी तक कुल 1887.73 लाख रुपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा की गयी है | अभी भी 758.44 लाख रुपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र समायोजित के लिए लंबित है | लंबित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अगले 7 दिनों के अंदर विभाग में जमा करें | कुल 253.85 लाख की राशि अभी खर्च नहीं हुआ है (पत्रांक-Camp दिनांक-08.01.15)

10. नगर सेवा प्रबंधन :-

आपके शहर से संबंधित इस वित्तीय वर्ष में हेल्पलाईन के माध्यम से 1 जन शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसका निराकरण किया गया है। स्पष्टतः आपकी उपलब्धि **संतोषजनक** है।

11. होलिडिंग टैक्स :- माह जुलाई 2016 का मासिक संग्रहण 2.49 लाख रुपये है, वित्तीय वर्ष 2016-17 की औसत मासिक संग्रहण 3.14 लाख रुपये है जो की वित्तीय वर्ष 2015-16 की औसत मासिक संग्रहण से 36.97 प्रतिशत अत्यधिक है। दिनांक 01.04.2016 को होलिडिंग की संख्या 8837 थी एवं अद्यतन तिथि तक 8868 होलिडिंग ही है। होलिडिंग का सर्वेक्षण करके अतिरिक्त होलिडिंग को होलिडिंग टैक्स के दायरे में लाने के लिए किये गये प्रयास जारी रहे।

12. अन्य स्रोतों से कर :-

अन्य स्रोतों से कर वसूली 13.29 लाख रुपये है, जिसमें सुधार लाने का प्रयास करें।

13. स्वच्छ भारत मिशन :- स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में दिए गए कुल लक्ष्य 439 एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 में दिए गए कुल लक्ष्य 878 अर्थात् कुल लक्ष्य 1317 के विरुद्ध आपके निकाय में 40 व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण किया गया है लेकिन एक भी सामूहिक एवं Public Toilet का निर्माण नहीं किया गया है | इस पर जोर दिया जाय।

14. पी०एल०खाता:- दिनांक 01.04.2016 को आपके नगर निकाय के पी० एल० खाते में 681.43 लाख रुपये उपलब्ध थे। वर्ष 2016-17 में 36.52 लाख राशि विमुक्त की गई है। इस प्रकार कुल उपलब्ध 717.95 लाख की राशि में से 184.04 लाख मात्र राशि का भुगतान किया गया है | शेष 533.91 लाख की अव्यवहृत अंतिम राशि (Closing Balance) अभी भी मौजूद है जो अत्यंत ही बड़ी राशि है।

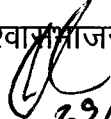
15. लंबित अंकेक्षण :-

आपके नगर निकाय के विरुद्ध निम्नलिखित अंकेक्षण प्रतिवेदन लंबित है :-

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं०	वर्ष	अनुपालन प्रतिवेदन की स्थिति
175/2006-07	2000-01 से 2011-12	अप्राप्त
128/2011-12	2008-09 से 2009-10	अप्राप्त
362/2012-13	2010-11 से 2011-12	अप्राप्त
692/2014-15	2012-13 से 2013-14	अप्राप्त

उपर्युक्त लंबित कंडिकाओ का निष्पादन अगले 7 दिनों के अंदर विभाग में जमा करें जिससे इसपर अग्रेतर कार्रवाई की जा सके ।

निर्देश दिया जाता है कि इस मासिक समीक्षा टिप्पणी में अंकित तथ्यों पर लिखित अनुपालन प्रतिवेदन पत्र निर्गत होने के तीन सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से विभाग को प्रेषित किया जाय। इस मासिक समीक्षा टिप्पणी को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जा रहा है। साथ ही आपके द्वारा समर्पित किये जा रहे मासिक समीक्षा टिप्पणी का अनुपालन प्रतिवेदन भी वेबसाईट पर अपलोड किया जाएगा।

विश्वामाजन

 29/8/2015
 (चैतन्य प्रसाद),
 प्रधान सचिव